रागदरबारी

सड़कछाप सड़क का दर्शनशास्त्र

सड़क का भी एक दर्शन होता है–खासकर उस सड़क का, जो खुद सड़कछाप हो। वह सड़क जो कहीं टिककर नहीं रहती, हर मोहल्ले, हर मोड़, हर चुनावी वादे में आवारगी करती मिल जाती है। आजकल ऐसी सड़कें खूब चलन में हैं–चलन में इसलिए कि चलने लायक कम और दिखने लायक ज्यादा होती हैं।

सड़क साम्यवाद का जीवंत, धूल-धूसरित उदाहरण है। यहाँ गधे और घोड़े एक ही ताल में चलते हैं–कभी-कभी तो पहचान ही गड़बड़ा जाती है कि कौन सा किस श्रेणी में है। पशु, पक्षी, मानव–सबको सड़क समान भाव से अपनाती है। सड़क सबकी माँ है। अब अगर माँ की गोद में बैठकर कोई पूछे कि गधे-घोड़े का फर्क क्यों नहीं दिख रहा, तो इसमें माँ का क्या दोष! सड़क तो बस बनी है–आओ, चलो, दौड़ो, गिरो, रौंदो–जो लिखा लाए हो, वही होगा। आप सड़क पर हैं या सड़क पर लाए गए हैं–यह नियति का मामला है, सड़क का नहीं।

सड़क और संसद का रिश्ता भी बड़ा दार्शनिक है। आदमी कब सड़क से संसद पहुँच जाए और कब संसद से सड़क पर लौट आए–कहा नहीं जा सकता। जनता सड़क के रास्ते ही नेताओं को संसद का पता देती है और उसी रास्ते से वापसी का न्योता भी। इसलिए सड़क है तो संभावनाएँ हैं–धरने की, हड़ताल की, रैली की, जाम की, और कभी-कभी नंगे नाच की भी। सड़क लोकतंत्र की खुली प्रयोगशाला है। सड़क है तो गड्ढे हैं। गड्ढे हैं तो मरम्मत है। मरम्मत है तो बजट है। बजट है तो फाइलें हैं। फाइलें हैं तो अफसर का चूल्हा जलता है। सड़क सरकार का बहुउद्देशीय औजार है–शौचालय, पेशाबघर और कचरा निस्तारण की कई योजनाओं से बचा लेती है। लोग सड़क पर ही अभ्यास कर लेते हैं, और सड़क राइट एट योर डोरस्टेप+ कचरा सेवा दे देती है–बिना टेंडर, बिना उद्घाटन। कोरोना के दिनों में जब सड़कें सूनी हुईं, तो उन्हें भी बुरा लगा। पर जल्दी ही फैक्ट्री मालिकों ने मजदूरों को निकाला और सड़कें फिर गुलज़ार हो गईं। मजदूरों के रेलों ने सड़कों को धन्य कर दिया–माँ की गोद फिर भर गई।

सड़कें हैं तो एक्सीडेंट हैं। ट्रैफिक पुलिस का डंडा अभियान निरंतर है। चालान से जेबें भी फूल टॉस फूल रही हैं । सड़कें हैं तो फुटपाथ हैं, और फुटपाथ हैं तो उन पर सोते लोग। वरना नशे में धुत रईसों को कुचलने के लिए लोग मिलेंगे कहाँ? सड़कें ही तो हैं जो रील और सेल्फी प्रेमियों की कर्मभूमि हैं–जहाँ जोखिम जितना बड़ा, व्यू उतने ज्यादा। सड़कें हैं तो सड़कछाप गुंडे भी हैं। राजनीति की प्रारंभिक पाठशाला यही है। रेहड़ियों से शुरू हुई हफ्तावसूली आगे चलकर बड़े घोटालों का पाठ्यक्रम बनती है। सड़क कैडर तैयार करती है–छुटभैये से गैंगस्टर तक। आजकल सड़कों पर ध्यान कम है। ध्यान दें भी तो कैसे–सड़कें बड़ी बेवफा हैं। बनाई नहीं कि उखड़ने को तैयार। इतना भी सब्र नहीं कि एक चुनावी कार्यकाल पूरा हो जाए। मरम्मत का बजट पास होते-होते नेता बदल जाता है और ज़ेडिट कोई और ले जाता है। समाधान सरल है–हर नेता अपने नाम की सड़क बनवाए। चुनाव हार जाए तो सड़क उठाकर घर ले जाए। सड़कें माँ जैसी हैं–बिल्कुल गाय की तरह। पान की पीक, कचरा, मल-मूत्र–सब समेट लेती हैं, बिना शिकायत। तभी तो आपने देखा होगा–गायें और उनके अधिकृत-अनधिकृत पतियों, यानी सांड–सड़क पर आराम से जुगाली करते हुए। स्टाफ का मामला है जी–जैसे रेलवे में टीटी अपने स्टाफ को सीट दिला ही देता है।

अब प्रश्न उठता है–माँ तो सड़क है, बाप कौन? हर कोई पूछता है, सड़क तेरे बाप की है क्या? पर बाप का पता आज तक नहीं चला। मिलते ही सूचना दी जाएगी।

कभी-कभी सड़कें उधड़ी हैं ताकि शहर को ग्रामीण जीवन की झलक मिल सके–कंक्रीट, धूल, मिट्टी–ज़मीन से जुड़े रहने का प्रशिक्षण। चिकनी सड़क पर खेलेंगे तो बच्चों की इम्युनिटी कहाँ बनेगी?

सड़कें पतित-पावनी भी हैं–मोक्षदायिनी। प्राचीन योगियों की परंपरा आज सड़कें निभा रही हैं–कहीं दुर्गम, कहीं अदृश्य, कहीं कीचड़, कहीं खाई। हैं भी, नहीं भी–ब्रह्मस्वरूप। फाइलों में हैं, वादों में हैं, पर चलने में अक्सर नहीं। न शुरुआत दिखती है, न अंत। कोई पूछे, +यह सड़क कहाँ जाती है?–भाग्यशाली हैं वे जिनकी जाती है। यहाँ तो सालों से देख रहे हैं–नज़र ही नहीं आती।

सड़कें वही हैं–जहाँ चाहो मोड़ लो, बिना शिकायत। और अगर सरकारी बजट की हों, तो नेता जी उन्हें अपने बंगले तक भी ले जा सकते हैं। सड़कछाप सड़क–बस महसूस करने की चीज़ है। मानने की, जानने की नहीं।

डॉ मुकेश असीमित

कार्टून कोना...

दतिया में ताल ठोकने को तैयार नरोत्तम

उपचुनाव की घोषणा से पहले ही दतिया में बढ़ा सियासी पारा

इंदौर। दतिया विधानसभा सीट को लेकर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती का 3 साल की सजा मिलने के साथ ही दतिया में उपचुनाव की संभावना बढ़ गई है। इस संभावना के साथ ही भाजपा नेताओं में मेल-मुलाकात का दौर शुरू हो गया है। इसे उपचुनाव की तैयारी से जोड़कर देखा हा रहा है। पूर्व गृह मंत्री और दतिया से भाजपा के पूर्व विधायक नरोत्तम मिश्रा की सक्रियता बढ़ गई है।

हालांकि पिछले चुनाव में उन्हें कांग्रेस के राजेंद्र भारती से हार का सामना करना पड़ा था। अब सीट खाली होने के बाद उनके फिर से चुनाव मैदान में उतरने की चर्चाएं तेज हैं। यानी 2023 में मिली हार का बदला लेने के लिए नरोत्तम दतिया उपचुनाव में ताल ठोकेंगे। उधर, कांग्रेस ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। फिलहाल सभी की नजरें 15 अप्रैल की अगली सुनवाई पर टिकी हैं क्योंकि इसके बाद ही दतिया उपचुनाव की स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। मप्र में वर्तमान में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे दतिया और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की संभावना बनी हुई है। प्रदेश में बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बाद सत्ताधारी दल में हलचल तेज हो गई है। दतिया सीट रिक्त घोषित होने के बाद पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दतिया में सक्रियता बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक शेर इज बैक और विन दतिया मिशन हैशटैग के साथ पोस्ट शेयर कर रहे हैं। पिछले एक सप्ताह से हर दूसरे दिन नरोत्तम दतिया पहुंचकर स्थानीय लोगों से मेल-मुलाकात कर रहे हैं। इधर, पूर्व मंत्री रामनिवास रावत ने विस अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की। दोनों के बीच बंद कमरे में चर्चा हुई। इस मुलाकात को भी ग्वोपुर जिले की विजयपुर सीट पर संभावित उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, रावत ने इसे शिष्टाचार भेंट बताया।

नरोत्तम की बढ़ी सक्रियता

पूर्व गृह मंत्री और दतिया से भाजपा के पूर्व विधायक नरोत्तम मिश्रा की सक्रियता बढ़ गई है। दतिया में सक्रियता के साथ ही वे भाजपा के नेताओं से भी लगातार मेल मुलाकात कर रहे हैं। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में हार के बाद वे सक्रिय राजनीति से दूर रहे। अब बैठकों और चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। नरोत्तम मिश्रा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के बीच गत दिवस भोपाल में बंद कमरे में सीक्रेट बैठक हुई। इस बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं कि उपचुनाव को लेकर चर्चा हुई होगी। साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में दतिया से राजेंद्र भारती को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था। वहीं, भाजपा ने नरोत्तम मिश्रा को मैदान में उतारा था। इस चुनाव में भारती को 88977 और नरोत्तम मिश्रा को 81235 वोट मिले थे। मिश्रा को 7742 वोटों से हार मिली थी।

6 महीनों में कराना होगा चुनाव

दरअसल, दिल्ली की एमपी-एमएलए कोर्ट ने दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को एफडी घोटाला मामले में दोषी पाया था और तीन साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले को चुनौती देने के लिए भारती ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। जहां अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। इसके साथ हाईकोर्ट ने मप्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उच्च न्यायालय अपने फैसले में बदलाव नहीं करता है तो भारती अयोग्य रहेंगे और दतिया विधानसभा सीट पर 6 महीने के भीतर चुनाव कराने होंगे। दतिया से कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भारती को तीन साल की सजा के विरुद्ध अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट में 15 को सुनवाई है। भारती ने हाई कोर्ट से अपनी सजा पर स्टे की मांग की है। उन्होंने फैसला आने तक दतिया में उपचुनाव पर रोक लगाने की भी गुहार लगाई है। हाई कोर्ट ने भारती की अपील पर मप्र सरकार और केंद्रीय चुनाव आयोग, दोनों से जवाब मांगा है। वहीं विजयपुर से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा की विधानसभा सदस्यता पर सुप्रीम कोर्ट 23 जुलाई को सुनवाई करेगा। तब तक के लिए कोर्ट ने उनके निर्वाचन को शून्य घोषित करने के फैसले पर स्टे दिया है। अपराध का ब्यौरा छिपाने के मामले में ग्वालियर हाई कोर्ट ने 9 मार्च को मल्होत्रा का निर्वाचन शून्य घोषित किया था।

कमलनाथ पर दांव लगा सकती हैं कांग्रेस

राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी में बन रही रणनीति

इंदौर। मप्र में राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भी हलचल तेज है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग रोकने की है। पार्टी आलाक्रमान मप्र से कांग्रेस के खाते में आने वाली इस इकलौती सीट को लेकर किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में नहीं है।

इसी रणनीति के तहत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को मध्यप्रदेश से राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा तेज हो गई है। पार्टी नेतृत्व को भी आशंका है कि मप्र में विधायकों में असंतोष की स्थिति बनी हुई है। इसका असर मतदान के दौरान दिख सकता है। ऐसे में एक मजबूत, प्रभावशाली चेहरे को उम्मीदवार बनाकर विधायकों को एकजुट रखने की कोशिश की जा रही है। कमलनाथ का नाम इसी कारण आगे आया है। कमलनाथ को राज्यसभा भेजने से पार्टी आलाकमान प्रदेश संगठन को यह संदेश भी देना चाहता है कि प्रदेश कांग्रेस में सब ठीकठाक है। साथ ही, यह कदम उन विधायकों को साधने में भी मददगार हो सकता है, जो हाल के दिनों में मप्र कांग्रेस के नेताओं से असहज नजर आए हैं। हालांकि, आधिकारिक तौर पर पार्टी की ओर से अभी तक कोई नाम तय नहीं किया गया है। जिस तरह लगातार फीडबैक लिया जा रहा है, उससे साफ है कि इस बार उम्मीदवार चयन में सावधानी बरती जाएगी। अभी तक चर्चा में जो नाम सामने आए हैं उनमें सबसे मजबूत दावेदारी पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन रही है। पर सभी विधायकों को एकजुट बनाए रखने आलाकमान किसी बड़े चेहरे की तलाश में है।

दिग्गज नेताओं का बढ़ेगा और कद

मप्र भाजपा की नई कोर कमेटी का ऐलान

इंदौर। मप्र में भाजपा की नई कोर कमेटी का बहुत जल्द ही ऐलान होने वाला है। क्योंकि 22 नेताओं के नाम दिल्ली में भेज दिए गए हैं। इन 22 नेताओं के नाम मंजूरी के लिए दिल्ली भेजते ही हलचल भी तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि कुछ बड़े और दिग्गज नेताओं की भूमिका और मजबूत हो सकती है। लेकिन इस पर फैसला आलाकमान ही लेगा। संभावना जताई जा रही है कि मप्र भाजपा की नई कोर कमेटी का ऐलान आज हो सकता है।

जानकारी के अनुसार, 14 अप्रैल को कोर कमेटी की पहली बैठक है जिसमें रणनीति पर मंथन होगा। चर्चा है कि 14 अप्रैल को कोर ग्रुप की संभावित बैठक में पुराने सदस्य ही शामिल होंगे, जिनके द्वारा प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की दिशा में सरकारों द्वारा किए जा रहे कार्यों को किस तरह से जन-जन तक पहुंचाया जाए। इस पर मंथन किया जाएगा। इसके अलावा यूसीसी और अन्य विषयों पर भी बैठक में चर्चा की जाएगी।

जानकारी के अनुसार, मप्र भाजपा के कोर ग्रुप में तीन महिला नेत्रियों को शामिल किया जा सकता है। इनके नामों पर दिल्ली से मुहर लगाई जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त है, जिसकी वजह नए कोर ग्रुप के नाम तय नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 14 अप्रैल को प्रस्तावित बैठक मौजूदा कोर ग्रुप ही करेगा। गौरतलब है कि प्रदेश कोर ग्रुप को नए सिरे से गठित किया जाना है। इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद प्रदेश भाजपा ने संभावित नामों की सूची तैयार की है। सूची को दिल्ली भेजा गया है, लेकिन संभावित सूची में महिला नेत्रियों की भागेदारी नहीं होने की वजह से सूची पर मुहर नहीं लग सकी है। कहा गया है कि सूची में 2 से 3 महिला नेत्रियों के अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व देने को भी कहा गया है। जिससे सूची को घोषित नहीं किया जा सका।

नए कोर ग्रुप में दिखेगा संतुलन

भाजपा से जुड़े सूत्रों की मानें तो नए कोर ग्रुप में एक विधायक महिला या कैबिनेट मंत्री, दो केंद्रीय मंत्री, प्रदेश संगठन के वरिष्ठ पदों पर बैठे किसी अनुसूचित जनजाति वर्ग से आने वाले वरिष्ठ नेता, राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय अनुसूचित जाति के नेता को शामिल किया जा सकता है। मध्यप्रदेश भाजपा की कमान संभालने के बाद हेमंत खंडेलवाल ने कोर ग्रुप की बैठकें बुलाने की पहल की थी।

इस पर बैठकें भी हुईं, लेकिन खंडेलवाल के कार्यकाल में अब तक केवल दो ही बैठकें हो सकी हैं और वह भी पहले से गठित कोर ग्रुप के सदस्यों के साथ। मौजूदा कोर ग्रुप का गठन वर्ष 2023 में किया गया था। नियमयानुसार नए अध्यक्ष के कार्यकाल में नया कोर ग्रुप गठित होना चाहिए, जिसके लिए पूरा कवायद की जा रही है। भाजपा की राष्ट्रीय टीम की घोषणा इस माह के अंत तक की जा सकती है, जिसमें मध्यप्रदेश से भी बड़ा प्रतिनिधित्व रहेगा। कहा जा रहा है कि अब मध्यप्रदेश की कोर ग्रुप की टीम तय करते वक्त भाजपा की संभावित राष्ट्रीय टीम को भी ध्यान में रखा जाएगा। यानि कि ऐसे नेता जिन्हें भाजपा की राष्ट्रीय टीम में स्थान दिया जाता है, तो उन्हें मध्यप्रदेश के कोर ग्रुप से दूर रखा जा सकता है। इस पर जल्द ही फैसला लिया जा सकता है। सूची में महिला नेत्रियों सहित कुछ नाम चौकाने वाले भी हो सकते हैं।

दिल्ली भेजी गई सूची में 22 नाम

कोर ग्रुप के लिए जो सूची प्रदेश भाजपा द्वारा केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई है, उसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित 22 नेताओं के नाम बताए जा रहे हैं। इनमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री वीरेन्द्र खटीक, उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा व राजेन्द्र शुक्ला, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पीडब्ल्यू डी मंत्री राकेश सिंह, पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव, अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, सांसद व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के नाम बताए जा रहे हैं।

इनके अलावा कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह, उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के अलावा पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया के नाम बताए जा रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व के निर्देश के बाद सूची में कुछ नाम बदले जा सकते हैं। इसमें महिला कोटे से केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर, सीधी विधायक रीति पाठक, सांसद लता वानखेड़े, विधायक अर्चना चिटनिस में से किसी दो नाम सूची में जोड़े जा सकते हैं।

जनाधार वाले नेता को भेजा जाए राज्यसभा

राज्यसभा की उम्मीदवारी पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने कहा

इंदौर। मप्र में राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से कांग्रेस के कब्जे वाली सीट पर दिग्विजय सिंह सांसद हैं। उनके तीसरी बार राज्यसभा जाने से इनकार करने के बाद कांग्रेस में केंडिडेट को लेकर रेस चल रही है। इस बीच राज्यसभा सीट पर उम्मीदवारी को लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि सच्चाई ये है कि न तो हमें कोई चाहता है, न कुछ होना है। दिन में सपने गोविंद सिंह नहीं देखा करते। डॉ. गोविंद सिंह ने उम्मीदवारों के नामों पर मंथन को लेकर कहा कि कांग्रेस अनुशासित पार्टी है, यहां कोई मंथन नहीं चल रहा है। हाईकमान को उम्मीदवार चुनने का अधिकार है। हमारी पार्टी के अध्यक्ष खरगे जी और राहुल जी जो निर्णय करेंगे, वही सर्वमान्य होगा। बीजेपी वाले तमाम लोग तोडऩे का प्रयास करेंगे, लेकिन असफल होंगे। डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि जब पूरा निर्णय हमारे हाईकमान पर है, तो राय देना उचित नहीं है। हालांकि, हमारा मानना है कि ऐसे जनाधार वाले नेता को राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए, जो आम जनता और पार्टी के हित में काम करे और लोगों के सुख-दुख में साथ खड़ा रहे। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतिनिधि प्रदेश में सक्रिय रूप से दौरा करे और भाजपा को आगामी चुनाव में हराने के लिए संघर्ष करे।

कांग्रेस से राज्यसभा के लिए ये नेता दावेदार

पूर्व सीएम कमलनाथ, पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन, पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, एससी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप अहिरवार के अलावा करीब एक दर्जन नेता राज्यसभा जाने के लिए प्रयासरत हैं। पूर्व सीएम और मौजूदा राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह और एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी राज्यसभा की रेस से खुद को अलग कर चुके हैं।

कटाक्ष

ग़ज़ल

साफ़ पानी जो न दे उस सरकार का क्या हो।
मज़लूमों से मिली उस फटकार का क्या हो।।

मुल्क के ख़िदमतगारों का गुस्सा ठीक नहीं,
फ़र्ज़ निभाते हैं जो उस पत्रकार का क्या हो।

लेनी ही होगी पूरी ज़िम्मेदारी हुक्मरानों को,
ज़िम्मेदारी छोड़ उनके अहंकार का क्या हो।

होती नहीं सल्तनत ज़ागीर किसी की कभी,
ज़ागीर जाने पर तुम्हारे धिक्कार का क्या हो।

देख लापरवाही रंजीदा है सारा शहर,
सोचें वे लोग तुम्हारे बात-विचार का क्या हो।

नाराज़गी महँगी पड़ेगी देखना वीरेन,
फिर कुरसी की तुम्हारी फुफ्कार का क्या हो।

वीरेन्द्र नारायण झा वीरेन
समया-मधुबनी-बिहार मिथिला